traffic is very heavy and people prefer road. People prefer seat route; from Kolkata to Chennai, Kolkata to Thoothukudi. Why Railways is not able to compete with them?

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, obviously, as far as sea routes are concerned, there is no question. That any mode of transport can compete with that. The ships can travel on different paths and there is no restriction on the number of paths, whereas, in Railway you need to start right from land acquisition, invest hundreds and thousands of crores of rupees, set up tracks and then tracks also become a restriction that how many trains you can run on the tracks.

As regards investment between Railways and roadways, obviously, the roads require much less investment. There is signalling system in the Railways for example which you don't need so elaborate in the roads. You don't need expensive railway tracks for roads. You don't need a large amount of maintenance infrastructure in roads compared to the Railways. So, it is like comparing an apple and an orange. The roads have their own importance and have completely different investment structure and operating cost. Railways is a much, much larger investment. But in terms of operating cost, Railways is more efficient because once you get a path, then the requirement of energy is much less and you can move larger volumes. So, it is a trade-off. For shorter distances, usually road is a better method; for medium term distances, rail is better; and for long distances, ship is better.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 67. Questioner is not present. *...(Interruptions)...*

एक माननीय सदस्य: सर, वे उपस्थित हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: डा. विकास महात्मे, आप अपनी सीट पर तो रहें।

Stubble burning in Punjab and Haryana

*67. DR. VIKAS MAHATME: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government is aware of the detrimental effects of the practice of stubble burning by farmers in North India, if so, the steps that have been taken in this regard;

(b) whether Government has any proposal for financial assistance to farmers to remove the stubbles from their farms to avoid burning in order to control the pollution in and around Delhi and NCR;

(c) whether a long-term action plan has been prepared to eliminate stubble burning in future, if not, reasons therefor; and

(d) the steps that have been taken in response to the Supreme Court's decision on ban on stubble burning?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI PARSHOTTAM RUPALA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Yes Sir. Paddy stubble burning is mainly practiced by the farmers in Indo-Gangetic plains of the States of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh to clear the fields for Rabi crop sowing. The farmers are resorting to paddy straw burning because of very short time window between the harvesting of paddy crop and the sowing of next crop. The fire events in the States of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh have been monitored through the satellite remote sensing and through several meetings and weekly video conferencing with the States at various levels. The machines and equipments for *in-situ* management of crop residue have been provided to the individual farmers on subsidy @ 50% of the cost and 80% of the project cost for establishment of Custom Hiring Centres, which will benefit the farmers in long run. As per satellite data, overall about 18.8% and 31% reduction in number of paddy residue burning events were observed in the year 2019 as compared to that in 2018 and 2017, respectively in these three States.

To address air pollution and to subsidize machinery required for in-situ management of crop residue, a Central Sector Scheme on 'Promotion of Agricultural Mechanization for *In-Situ* Management of Crop Residue in the States of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and NCT of Delhi' is being implemented and the funds of the tune of ₹ 584.33 crores in 2018-19 and 594.14 crores in 2019-20 have been released under this scheme.

Out of these funds, the State Governments during 2018-19 and 2019-20, have supplied more than 100610 machines to the individual farmers and to the Custom Hiring

Centres on subsidy for *in-situ* management of crop residue. The State Governments and Krishi Vigyan Kendras (KVKs) have also undertaken Information, Education and Communication (IEC) activities on a massive scale for creating awareness among farmers. The State Governments are also promoting the *ex-situ* management of paddy residue by way of utilizing it in biomass based power plants, production of bioethanol and Bio-CNG.

(d) In compliance to the directions of Supreme Court *vide* order dated 06.11.2019, the Government of Punjab has implemented a scheme for providing compensation @ ₹ 100/- per quintal to those small and marginal farmers who are cultivating non-basmati paddy and are managing the paddy residue by *in-situ* method without burning. The Government of Haryana also brought out the scheme to provide ₹ 1000/- per acre operational charges for crop residue management for *in-situ* and *ex-situ* purposes. The Government of Haryana also provided ₹ 100 per quintal incentive to those farmers who have sold their paddy after 06.11.2019 and till 15.11.2019 and have not burnt the crop residue.

डा. विकास महात्मे: मेरा पहला सवाल यह है कि यह जो पराली जलाने से या पुआल जलाने से air pollution हो रहा है, तो air pollution कम हो और लोग air pollution के बारे में aware हों, इसके लिए क्या सरकार के विचार में हर जगह air quality index boards लगाने की कोशिश हो रही है?

श्री परशोत्तम रुपाला: सर, महात्मे साहब ने जो बताया कि air pollution के सूचकांक को लोगों की जानकारी में आने के लिए वे साधन लगाने चाहिए, तो वे वैदर नियंत्रण विभाग की ओर से हमने जरूर लगाये हुए हैं और इनकी जानकारी भी प्राप्त होती है। उनको मैं एक अच्छा जवाब भी देता हूँ। पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर वायु गुणवत्ता का डेटा जारी किया, जिसमें दर्शाया गया है कि 2017 के दौरान वायु गुणवत्ता का सूचकांक PM 273 था, जो नवम्बर, 2018 के दौरान 132 हो गया।

श्री उपसभापति: आप दूसरा सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछिए।

डा. विकास महात्मे: सर, इसमें बताया गया था कि वायु प्रदूषण काफी कम हुआ है, 33 परसेंट से भी कम हुआ है। मेरा सवाल यह है कि क्या यह zero तक जल्दी पहुँच पायेगा? ...**(व्यवधान)**... साथ ही, सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की जाएगी?

श्री परशोत्तम रुपाला: उपसभापति महोदय, वैसे मैं बताना चाहूँगा कि पराली के सब्जेक्ट को लेकर जो डिबेट चल रही है, तो यह कुल pollution का 3 परसेंट ही है। इसको 100 per

[श्री परशोत्तम रुपाला]

cent खत्म कर देने के बाद भी हम केवल उसी को समाप्त कर सकते हैं, मगर हम चाहते हैं कि हम सब नागरिकों को पूरे शुद्ध वायुमंडल की उपलब्धि मिले।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ धान और उसके बाद सबसे ज्यादा क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है। गन्ने का जो फसल अवशेष है, जिसे हम 'पत्ती' बोलते हैं, पहले उसका उपयोग कोल्हू में गुड़ बनाने के लिए और कच्चे मकानों में छप्पर बनाने में उपयोग होता था, लेकिन अब उसका उपयोग कम हो गया। किसान उसे जलाने पर मजबूर है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: नागर जी, आप अपना सवाल पूछिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नाम पर ऐसे किसानों पर FIR की जा रही है, तो क्या सरकार इस 'पत्ती' को जैविक खाद या अतिरिक्त ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने पर कोई विचार कर रही है और इसमें किसान के ऊपर जो अतिरिक्त भार आयेगा, उसको मनरेगा से जोड़ने का कोई विचार सरकार कर रही है? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: धन्यवाद, नागर जी। Already एक सवाल हो गया।

श्री परशोत्तम रुपाला: उपसभापति जी, माननीय सांसद का यह सवाल बिल्कुल जरूरी है। जैसे पराली के बारे में ही हम सब डिबेट करते हैं, मगर वहां गन्ना किसानों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर विभाग की ओर से जो हमारी पॉलिसी थी, वह लास्ट 31 तारीख को खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हमें नई पॉलिसी बनानी है और नई पॉलिसी बनाने के लिए हमने सारे राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर ली है। उसमें आपके इनपुट्स भी हों, तो वे इनपुट्स भी आप हमें दे देना। मैं चाहूंगा कि इन सभी स्टेक होल्डरों के साथ बैठकर जिसमें इन सारी समस्याओं के समुचित समाधान हों, ऐसी नई पॉलिसी हम तुरंत ही ज़ाहिर कर देंगे।

सरदार बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब): डिप्टी चेयरमैन साहब, आपके ज़रिये मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सबसे बड़ी समस्या है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जतन कर रही और सरकार भी जतन कर रही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो पहले जतन किये हैं, उनको सौ प्रतिशत इम्प्लिमेन्ट करने के लिए ओपन मार्केट से जो लेटेस्ट मशीनरी है, वह फार्मर्स को दी जाए। अभी ओल्ड मशीनरी मिल रही है और पैसा जाया जा रहा है। लेटेस्ट न्यू मशीनरी सौ प्रतिशत किसानों के पास जाए, यह डायरेक्ट फार्मर्स को दी जाए और थ्रू ओपन मार्केट दी जाए। दुकानें नियत कर दी जाती हैं, जहां वे बाहर स्मग्लिंग होती है।

श्री उपसभापति: माननीय बलविंदर सिंह जी, आप सवाल पूछिए।

सरदार बलविंदर सिंह भुंडर: इसलिए ओपन मार्केट से लेटेस्ट मशीनें फार्मर्स को मिलें।

श्री परशोत्तम रुपाला: माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। अभी तक हम मशीनें सब्सिडी देकर मुहैया करा रहे हैं। हम इनडिविजुअल किसानों को दे रहे हैं और ग्रुप्स तथा पैक्स सभी को दे रहे हैं। इसमें आपका जो सुझाव है कि ओपन मार्केट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो भी यंत्र होंगे, उन्हें भी हम अपनी इस योजना में शामिल करेंगे।

Impact of climate change on agricultural practices

*68. SHRI MD. NADIMUL HAQUE: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Ministry has taken cognisance of the impact of climate change on agricultural practices and crop cycles in the country;

(b) if so, the steps Government is taking for development of eco-friendly, adaptive agricultural practices; and

(c) if not, by when does Government plan to do so?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI PARSHOTTAM RUPALA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, taking the cognisance of the impact of Climate Change on agricultural practices and crop cycles in the country, the Govt. has launched the National Action Plan on Climate Change (NAPCC) during 2008.

The National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA), which is one of the eight Missions under the (NAPCC) seeks to address issues regarding 'Sustainable Agriculture' in the context of risks associated with climate change by devising appropriate adaptation and mitigation strategies for ensuring food security, equitable access to food resources, enhancing livelihood opportunities and contributing to economic stability